



भारत का राजपत्र

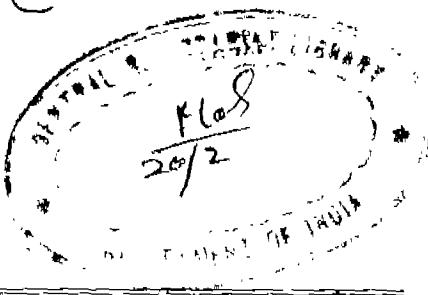
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 549]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2002/ज्येष्ठ 29, 1924

No. 549]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2002/JYAIKTHA 29, 1924

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वैकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2002

का.आ. 648(अ).—केन्द्र सरकार ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10)की धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए आवेदन पर उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन बनारस स्टेट बैंक लि०, वाराणसी के संबंध में अधिस्थगन आदेश दिया है :

और भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे अधिस्थगन के दौरान अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित और निषेपकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनारस स्टेट बैंक लि० का बैंक आफ बड़ौदा में समामेलन की योजना तैयार की थी :

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त धारा की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में संबंधित बैंकों को योजना का प्रारूप भेजने के पश्चात तथा उक्त योजना के संबंध में प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् इसे मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को भेज दिया था :

और केन्द्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त सुझावों और आपत्तियों पर की गई टिप्पणियों के आलोक में उन सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया है :

अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर और उसके अधीन रहते हुए निम्नलिखित योजना को मंजूरी देती है ।

अध्याय-1प्रारंभिक1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इस योजना को बनारस स्टेट बैंक लि. (बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समामेलन) योजना, 2002 कहा जाये ।
- (2) यह उस तारीख से लागू होगी जिसे (इसके बाद निर्धारित तारीख के रूप में जानी जायेगी) केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

2. परिभाषाएँ :

इस योजना में यदि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो तो -

- (1) "अधिनियम" से अभिप्राय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) से है ।
- (2) "आस्ति खाता" से अभिप्राय उस काल्पनिक खाते से है जो उक्त अंतरक बैंक की देयताओं को समय-समय पर समायोजित करने के बाद अधिशेष अथवा कमी का पता करने के लिए योजना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (2) के अनुसरण में खोला गया हो ।
- (3) "संग्रहण खाता" से अभिप्राय उस काल्पनिक खाते से है जो आस्तियों और देयताओं के समायोजन के बाद अंतरक बैंक के सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध होनेवाली राशि का, यदि कोई हो, पता लगाने के प्रयोजन हेतु योजना के पैराग्राफ 7 के अनुसरण में खोला गया हो ।
- (4) "निर्धारित तारीख" से अभिप्राय उस तारीख से है जिसे पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ (2) के अंतर्गत केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट करे ।
- (5) "योजना" से अभिप्राय बनारस स्टेट बैंक लि. (बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समामेलन) योजना, 2002 है ;
- (6) "अंतरक बैंक" से अभिप्राय बनारस स्टेट बैंक लि. नामक बैंकिंग कंपनी से है, जिसका पंजीकृत कार्यालय वाराणसी में स्थित है ;
- (7) "अंतरिती बैंक" से अभिप्राय बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अंतर्गत गठित तदनुरूपी एक नया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है ;

- (१) यहां प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी प्रेरिताबासा नहीं दी गयी है परंतु उक्त अधिनियम में जिनकी परिभासा दी गई है, अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम में दिया गया है ।

अध्याय - II

कारोबार, संपत्तियों, आस्तियों और देयताओं का अंतरण

3. आस्तियों और देयताओं का अंतरण तथा उसका सामान्य प्रभाव :

(1) निर्धारित तारीख को तथा उक्त तारीख से अंतरक बैंक के सभी अधिकार, शक्तियां, दावे, मांगें, हित, प्राधिकार, विशेषाधिकार, लाभ, आस्तियां और अचल और सचल संपत्तियां, जिनमें परिसर शामिल हैं, जो भूमिति (अवधि) की सभी अनुशंसियों और जिस पट्टे या करार के अंतर्गत उन्हें धारित किया गया है उसमें आरक्षित या निहित कियाये की राशियों तथा अन्य राशियों और प्रसंविदाओं के अधीन होंगे तथा कार्यालय का सभी फर्नीचर, खुले रखे गये उपकरण, संयंत्र उपकरण और साधन सामग्री, बहियां, कागज, लेखन-सामग्री का स्टॉक, अन्य स्टॉक और भंडार, स्टॉक शेयरों और प्रतिभूतियों में सभी निवेश, हाथ में तथा मार्गस्थ सभी प्राप्य बिल, हाथ में समस्त नकदी तथा बैंकों में चालू अथवा जमा खाते (जिसमें मांग अथवा अल्पकालिक सूचना पर धन राशि शामिल है) में समस्त नकदी, सोना-चांदी, सभी बही ऋण, बंधक ऋण तथा उनके लिए प्रतिभुओं अथवा किसी गारंटी के लाभ सहित अन्य ऋण, अंतरक बैंक के कारोबार के संबंध में सभी अन्य संपत्ति अधिकार और सभी गारंटियों का आस्ति लाभ, यदि कोई हों, इस योजना के अन्य उपबंधों के अधीन अंतरिती बैंक को अंतरित मानी जायेगी तथा वे उसकी संपत्तियां और आस्तियां होंगी और निर्धारित तारीख से अंतरक बैंक की सभी देयतायें, शुल्क और बाध्यतायें यहां आगे दी गयी सीमा और ढंग से अंतरिती बैंक की देयतायें, शुल्क और बाध्यतायें होंगी ।

(2) ऊपर दिये गये प्रावधानों को सामान्य रूप से प्रभावित किये बिना सभी संविदाएं, विलेख, बांड, करार, मुख्तारनामे (पॉवर ऑफ अटर्नी), विधि सम्मत प्रतिनिधित्व की मंजूरियां तथा किसी भी स्वरूप के विद्यमान अथवा निर्धारित तारीख से तुरंत पहले प्रभावी अन्य लिखत आगे बतायी गयी सीमा तक और ढंग से अंतरिती बैंक के विरुद्ध या पक्ष में प्रभावी होंगे तथा उन पर इस तरह से कार्रवाई की जायेगी मानो अंतरक बैंक के बजाय अंतरिती बैंक उनकी एक पार्टी हो अथवा मानो वे अंतरिती बैंक के पक्ष में जारी किये गये हों ।

(3) यदि निर्धारित तारीख को कोई मुकदमा, अपील अथवा किसी भी तरह की कोई अन्य विधिक प्रक्रिया अंतरक बैंक द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अनिर्णीत हो तो वह छोड़ी नहीं जायेगी अथवा रोकी नहीं जायेगी अथवा किसी भी प्रकार से उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वह इस योजना के अन्य उपबंधों के अधीन होगी और अंतरिती बैंक द्वारा अथवा उसके विरुद्ध निष्पादित और प्रवर्तित होगी ।

(4) यदि भारत से बाहर किसी देश के कानून के अनुसार इस योजना के प्रावधान उस देश में स्थित किसी आस्ति अथवा देयता के, जो अंतरक बैंक के कारोबार का या अंतरिती बैंक के दायित्व का भाग हो, अंतरण अथवा उसको निहित करने के लिए स्वयं में प्रभावी न हों तो ऐसी आस्तियों अथवा देयताओं के संबंध में अंतरक बैंक के मामले निर्धारित तारीख को अंतरिती बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपे गये माने

—येंगे और मुख्य कार्यपालक अधिकारी उसके कार्यों का प्रभावशाली ढंग से परिसमापन करने के प्रयोजन हेतु सभी शक्तियों का उसी प्रकार इस्तेमाल करेगा जैसे कि वे अंतरक बैंक द्वारा इस्तेमाल की गयी हों। मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार के अंतरण को प्रभावी बनाने अथवा निहित करने के प्रयोजन हेतु ऐसे सभी कदम उठायेगा जो भारत से बाहर उस देश के कानून द्वारा अपेक्षित हों और उसके संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा इस काम के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अंतरक बैंक की किसी भी आस्ति की वसूली करेगा अथवा उसकी देयता की पूर्ति करेगा तथा शुद्ध आगम राशियों को अंतरिती बैंक को अंतरित करेगा।

4. अंतरक बैंक की बहियां बंद करना और तुलनपत्र तैयार करना :

(1) अंतरक बैंक की बहियां बंद की जायेंगी और उनका तुलन किया जायेगा तथा पहली बार उनका तुलनपत्र दिनांक 22 जनवरी 2002 को तैयार किया जायेगा और उसके बाद निर्धारित तारीख के ठीक पहले की तारीख को कारोबार बंद करने की स्थिति के अनुसार बंद की जायेंगी और उनका तुलन किया जायेगा तथा तुलनपत्र तैयार किया जायेगा और उक्त तुलनपत्र का लेखा-परीक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित या नामित किसी सनदी लेखाकार अथवा सनदी लेखाकारों की किसी फर्म के द्वारा करवाया जायेगा और उसको प्रमाणित करवाया जायेगा।

(2) पूर्वगामी पैराग्राफ के उपबंधों के अनुसार तैयार की गयी अंतरक बैंक के तुलनपत्र की प्रति प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र अंतरक बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की जायेगी और उसके बाद अंतरक बैंक को तुलनपत्र अथवा लाभ-हानि खाता तैयार करने अथवा उसे सदस्यों को प्रस्तुत करने अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उक्त प्राधिकारी के पास प्रतियां प्रस्तुत करने अथवा तुलनपत्र और खातों पर विचार करने या किसी अन्य प्रयोजन हेतु बोर्ड की बैठक या वार्षिक आम सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5. आस्तियों का मूल्यन और देयताओं का निर्धारण:

अंतरक बैंक के परामर्श से अंतरिती बैंक अंतरक बैंक की संपत्ति और आस्तियों का मूल्यन करेगा और उसकी देयताओं का निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुमान लगायेगा, अर्थात् :

(1) (क) सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों का मूल्यन निर्धारित तारीख से ठीक एक दिन पहले प्रचलित बाजार दर पर किया जायेगा।

(ख)(i) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के प्रयोजन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, निर्धारित तारीख के ठीक एक दिन पहले की स्थिति पर किया जायेगा।

(ii) डाकघर प्रमाणपत्रों, खजाना बचत जमा प्रमाणपत्रों और किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों अथवा केन्द्र सरकार की अल्प बचत योजना के अंतर्गत जारी किये गये प्रमाणपत्रों जैसी केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों

व मूल्यन उनके अंकित मूल्य अथवा उस तारीख को नकदीकरण योग्य मूल्य, जो भी उच्चतर हो, पर किया जायेगा ।

(iii) ऐसी स्थिति में जहां जमींदारी उन्मूलन बांडों जैसी किसी सरकारी प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य प्रतिभूति के बाजार मूल्य का, जिसके संबंध में मूलधन का भुगतान किस्तों में किया जाना है, निर्धारण नहीं किया जा सकता अथवा किसी अन्य कारण से बाजार मूल्य को उसका सही मूल्य प्रकट करना नहीं माना जाता है अथवा अन्यथा उचित नहीं माना जाता है तो उस प्रतिभूति का मूल्यन मूलधन की किस्तों और अदा करने के लिए शेष ब्याज, इस प्रकार की किस्तों के देय रहने की अवधि, जिस सरकार की प्रतिभूति हो उस सरकार द्वारा जारी की गयी उसी अवधि की अथवा लगभग उसी अवधि की किसी प्रतिभूति पर प्रतिफल तथा अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए उचित समझी गयी राशि पर किया जायेगा ।

(ग) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड अथवा अन्य निवेश का बाजार मूल्य असामान्य बातों द्वारा प्रभावित होने के कारण उचित नहीं माना जाता है तो वहां निवेश का मूल्यन किसी उचित अवधि पर उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जायेगा ।

(घ) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड अथवा अन्य निवेश का बाजार मूल्य निर्धारण योग्य नहीं है वहां केवल वही मूल्य, यदि कोई हो, उचित माना जायेगा जो जारी करनेवाले प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, पिछले पांच वर्षों में अदा किये गये लाभांश तथा अन्य प्रासंगिक बातों को भी ध्यान में रखते हुए उचित माना जाये ।

(ङ) परिसरों तथा अन्य सभी अचल संपत्तियों और दावों को पूरा करने के लिए अभिग्रहीत आस्तियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर किया जायेगा ।

(च) फर्नीचर और फिक्सचर, स्टॉक में लेखन-सामग्री तथा यदि कोई हों तो अन्य आस्तियों का मूल्यन बहियों में लिखे गये हासित मूल्य अथवा वसूली योग्य मूल्य पर जैसा भी उपयुक्त समझा जाये, निर्धारित किया जायेगा ।

(छ) खरीद और भुनाये गये बिलों सहित अग्रिमों, बही ऋणों और विविध आस्तियों की अंतरिती बैंक संवीक्षा करेगा और प्रतिभूतियों और उनके जोखिम के लिए दी गयी गारंटीयों की जांच और सत्यापन अंतरिती बैंक करेगा । उसके बाद अग्रिमों को उनके अंशों सहित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा अर्थात् "लाभकर और तत्काल वसूलीयोग्य समझे गये अग्रिम" और "तत्काल वसूली योग्य न माने जानेवाले और / अथवा वसूली के लिए अशोध्य और संदिग्ध समझे गये अग्रिम" ।

(2) अंतरिती बैंक निर्धारित तारीख को "आस्ति खाता" के रूप में एक खाता खोलेगा । इस खंड के अनुसार तत्काल वसूलीयोग्य आस्तियों के रूप में निर्धारित आस्तियों के मूल्य से संबंधित कुल राशि "आस्ति खाते" में जमा लिखी जायेगी ।

(3) (i) जहां किसी आस्ति का मूल्यन निर्धारित तारीख को निश्चित नहीं हो सकता, उसे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से बाद की तारीख को अंशतः या पूर्णतः वसूली योग्य आस्ति माना जायेगा ।

(ii) किसी आस्ति के मूल्यन और / अथवा किसी अग्रिम के वर्गीकरण और / अथवा किसी देयता के निर्धारण के संबंध में अंतरिती बैंक और अंतरक बैंक के बीच असहमति की स्थिति होने पर उक्त मामला भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जायेगा और जिसकी राय अंतिम होगी, परंतु ऐसी राय प्राप्त होने तक उक्त मद या उसके किसी भाग का मूल्यन इस योजना के प्रयोजनों के लिए अंतरिती बैंक द्वारा अनंतिम रूप में स्वीकार किया जायेगा ।

(iii) रिजर्व बैंक के लिए यह उचित होगा कि यदि ऐसा करना उसके लिए आवश्यक हो तो आस्ति की किसी ऐसी मद के मूल्यन या देयता की किसी ऐसी मद के निर्धारण के संबंध में उपयुक्त समझा गया कोई तकनीकी परामर्श प्राप्त करे और ऐसा परामर्श प्राप्त करने की लागत राशि पूर्णतया अंतरक बैंक की आस्तियों में से देय होगी ।

(4) इस योजना के प्रयोजनों के लिए देयताओं में वे सभी प्रासंगिक देयताएं शामिल होंगी जिन्हें निर्धारित तारीख को या उसके बाद उपयुक्त रूप से उसके अपने संसाधनों से पूरा करने की अंतरिती बैंक से अपेक्षा की जायेगी ।

(5) पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार किया गया आस्तियों का मूल्यन और देयताओं का निर्धारण दोनों बैंकों और उनके सदस्यों तथा ऋणदाताओं को मान्य होगा ।

अध्याय - III

ऋणदाताओं को और जमाकर्ताओं को भुगतान

6. अंतरक बैंक की देयता का निष्ठान:

अंतरक बैंक की संपत्ति और आस्तियों के अंतरिती बैंक को अंतरित करने के प्रतिफलस्वरूप अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक की देयताओं को इस खंड तथा निम्नलिखित खंडों में वर्णित सीमा तक पूरा करेगा, अर्थात् :

(क) अंतरक बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा स्टाफ जमानत जमाराशियों के रूप में बैंक के पास जमा की गयी किसी राशि का, उस पर निर्धारित तारीख तक उपचित ब्याज सहित, यदि कोई हो, तथा निर्धारित तारीख को अन्य सभी बाल्य देयताओं का पूरा भुगतान किया जायेगा या उसके लिए प्रावधान किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण

इस उप पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ किसी जमाराशि पर निर्धारित तारीख तक देय ब्याज संबंधित जमाराशि का अंश माना जायेगा ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत देय सीमा तक ब्याज सहित, अंतरक बैंक के पास रखे प्रत्येक बचत बैंक खाते या चालू खाते या किसी अन्य जमा खाते, चाहे उसका जो भी नाम हो, तथा खंड (क) द्वारा समाविष्ट न किये गये अन्य प्रत्येक के संबंध में, अंतरिती बैंक निर्धारित तारीख को अपने पास, संबंधित धारक (कों) के

न में तदनुरूपी और समान खाता खोलकर निर्धारित तारीख को इस योजना के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकित पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट आस्तियों में से प्रत्येक खाते के संबंध में उपलब्ध यथानुपात अंश जमा करेगा। ऐसा करने के पहले इस प्रकार मूल्यांकित आस्तियों से तुरंत वूसली योग्य न माने गये अथवा अशोध्य अथवा संदिग्ध वसूली वाले अग्रिमों को; निर्धारित तिथि को मूल्यांकित न की गयी किसी आस्ति या आस्ति के अंश को तथा उक्त खंड (क) में वर्णित किसी अदायगी या प्रावधान के लिए आवश्यक किसी राशि को निकाल दिया जाएगा तथा इस प्रकार मूल्यांकित आस्तियों में 22 जनवरी 2002 को जारी अधिस्थगन आदेश के पैराग्राफ 2 के खंड (क)(i) के अनुसार अंतरक बैंक को की गयी अदायगी की कुल राशि जोड़ दी जाएगी।

बशर्ते 22 जनवरी 2002 को कारोबार की समाप्ति पर, या उसके बाद और निर्धारित तिथि से पूर्व जमा खाते से की गयी किसी भी अदायगी को इस उप-पैराग्राफ के अंतर्गत जमा की जानेवाली राशि के रूप में माना जायेगा और तदनुसार जमा की जानेवाली राशि यथानुपात अंश में से ऐसी अदायगी की राशि को घटाने के बाद बची राशि होगी।

इसके अलावा यदि अंतरिती बैंक को किसी विशेष जमा खाते में की गयी प्रविष्टियों के सही होने के बारे में कोई तर्कसंगत संदेह हो तो रिजर्व बैंक के अनुमोदन से यह अंतरिती बैंक द्वारा ऐसे खाते में सही शेष राशि का पता लगा लिये जाने तक, उक्त खंड (ख) के अनुसार उस खाते में राशि जमा करने पर रोक लगा देगा।

स्पष्टीकरण

‘यथानुपात’ शब्द से, जहां तक उसका प्रयोग इस पैराग्राफ में हुआ है, निर्धारित तिथि से ठीक पहले की तारीख तक देय ब्याज सहित 22 जनवरी 2002 को कारोबार की समाप्ति पर देय रहनेवाली संबंधित राशि के अनुपात में अभिप्रेत है तथा, जहां तक उसका प्रयोग इस योजना में अन्यत्र हुआ है, इससे ‘अदायगी अथवा वितरण के समय देय रहनेवाली संबंधित राशि के अनुपात में’ अभिप्रेत है।

(ग) उक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि जमा किये जाने के बाद अंतरिती बैंक, न्यूनतम संभव देरी सहित परंतु किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि से अधिक-से-अधिक तीन माह के भीतर, निश्चेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्थापित निश्चेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (इसके बाद इसे निगम कहा गया है) को उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षाओं का हर तरह से पालन करते हुए एक सूची भेजेगा और उसके बाद जब कभी उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशि निगम से प्राप्त हो, अंतरिती बैंक उक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक खाते में, राशियां प्राप्त होने की तारीख या तारीखों से सात दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अनुसार उस खाते में देय राशियां जमा करेगा :

बशर्ते -

(i) यदि उक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई खाता बंद हो गया हो अथवा वह उस समय अदायगी के लिए अवधिपूर्ण हो गया हो जब निगम से उस खाते में जमा करने के लिए कोई राशि प्राप्त हुई हो, तो अंतरिती बैंक द्वारा उक्त राशि के हकदार व्यक्ति को नकद अदायगी की जायेगी;

(ii) यदि उक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी राशि के हकदार व्यक्ति को ढूँढ़ा न जा सके या उसे तुरंत खोजना संभव न हो तो ऐसे व्यक्ति को देय राशि के लिए प्रावधान किया जायेगा तथा उसका निगम की बहियों में ही अलग से लेखांकन किया जायेगा तथा निगम के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अंतरिती बैंक को राशि अदा करे जब तक कि उस राशि का हकदार व्यक्ति ढूँढ़े न लिया जाये या उसका पता न लगा लिया जाये तथा निगम अंतरिती बैंक के माध्यम से उस व्यक्ति के संबंध में अदायगी करने का निर्णय न ले ले ।

अध्याय IV

7. अंतरक बैंक के सदस्यों के अधिकार और दायित्व

(1) निर्धारित तारीख को, अंतरक बैंक की चुकता पूंजी की संपूर्ण राशि और प्रारक्षित निधियां अंतरक बैंक के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अन्य आस्तियों में मूल्यहास के लिए किये गये प्रावधान के रूप में मानी जायेंगी तथा अंतरक बैंक के सदस्यों के अधिकार, अंतरिती बैंक के संबंध में, नीचे दिये गये अनुसार होंगे :

(अ) पूर्ववर्ती पैराग्राफ के खंड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक खाते के संबंध में, उस खंड और खंड (ग) के अनुसार जमा किये जाने के लिए बाकी रहनेवाले खाते के शेष, यदि कोई हो, और

(आ) अंतरक बैंक में प्रत्येक शेयरों के संबंध में उस राशि को जिसे निर्धारित तारीख से ठीक एक दिन पहले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा या उसकी ओर से शेयर पूंजी के लिए अदा किया गया माना गया था और/या नीचे खंड (i) के अनुसरण में अंतरिती बैंक द्वारा मांगी गयी राशि के रूप में शेयर पूंजी हेतु अदा किया गया माना गया था, उसे संग्रहण लेखे के रूप में माना जाएगा और अंतरिती बैंक की बहियों में उसे उसी रूप में दर्ज किया जाएगा तथा उक्त खाते से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किये जायेंगे, जैसे :

(i) (क) प्रथमतः, अंतरिती बैंक प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो अंतरक बैंक में आस्थगित शेयर के धारक के रूप निर्धारित तारीख को पंजीकृत था (अथवा इस रूप में पंजीकृत करने के लिए पात्र माना गया होता), यथानिर्दिष्ट तारीख अथवा तारीखों से तीन महीने में ऐसे शेयर या शेयरों और बकाया मांग राशि, यदि कोई हो, के संबंध में उसके द्वारा अद्तत रही मांगी न गयी राशि अदा करने को कहेगा और उसके बाद, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो निर्धारित तारीख को अंतरक बैंक के साधारण शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत था (अथवा इस रूप में पंजीकृत करने के लिए पात्र माना गया होता) यथानिर्दिष्ट तारीख अथवा तारीखों से तीन महीने में ऐसे शेयर अथवा शेयरों या बकाया मांग राशि, यदि कोई हो, के संबंध में उसके द्वारा अद्तत रही मांगी न गयी राशि अदा करने को कहेगा ।

(ख) अंतरिती बैंक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चूक की अवधि के लिए छः प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित उपर्युक्त उप खंड (क) के अंतर्गत देय राशियों की मांग और भुगतान करने के लिए यथासंभव सभी उपाय करेगा ।

(ii) अंतरिती बैंक अग्रिमों, खरीदे और भुनाये गये बिलों, बही ऋणों और विविध ऋणों तथा अन्य आस्तियों के संबंध में जिन्हे ‘आसानी से न वसूले जाने योग्य और / या वसूली के लिए अशोध्य और संदिक्षित’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, या जो उपर्युक्त पैराग्राफ 5 में निर्धारित तारीख के बाद पूर्णतः या अंशतः वसूलीयोग्य हैं या हो सकते हैं, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मांग और भुगतान करने के लिए यथासंभव सभी उपाय करेगा, और

(क) देनदार या किसी अन्य व्यक्ति के साथ समझौता या व्यवस्था करेगा या ऐसे ऋण या आस्ति को बद्दे खाते डालेगा ;

(ख) उसे अंतरित की गयी किसी प्रतिभूति या उसके द्वारा ली गयी किसी आस्ति की बिक्री करेगा या अन्य प्रकार से निपटान करेगा ।

(iii) इसके अलावा, अंतरिती बैंक उक्त अधिनियम की धारा 45ज के साथ पठित धारा 45ठ के अधीन अंतरक बैंक के किसी प्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा नुकसानी के रूप में अधिनिर्णीत की गयी राशि की, यदि कोई हो, मांग या भुगतान करने के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव सभी उपाय करेगा ।

(iv) अंतरिती बैंक ऊपर खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित मर्दों के कारण अपने द्वारा की गयी वसूलियों में से किसी आकस्मिक देयता के संदर्भ में उस सीमा तक भुगतान करेगा या प्रावधान करेगा जिस सीमा तक पैराग्राफ 6 (क) के अधीन उसके लिए किया गया प्रावधान अप्रयोगित हो, साथ ही रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से किसी देयता के संदर्भ में, चाहे वह आकस्मिक हो अथवा समग्र, जिसका उपर्युक्त पैराग्राफ 5 के संदर्भ में अनुमान नहीं लगाया गया था और जो निर्धारित तारीख को या उसके बाद उत्पन्न हुई है या पता लगी है, भुगतान करेगा या प्रावधान करेगा ।

(v) अंतरिती बैंक, उपर्युक्त खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित मर्दों के कारण उसके द्वारा की गयी वसूलियों में से, उक्त प्रयोजन के लिए हुए खर्च तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से उपर्युक्त समझे गये ऐसे अन्य खर्चों एवं उपर्युक्त खंड (iv) के अनुसार उसमें से विनियोजित राशि को घटाकर या इस योजना के प्रयोजनार्थ आकस्मिक देयताओं के संबंध में निश्चित किये गये प्रावधान में से ऐसी देयताओं के अंतिम रूप से निश्चित कर लिये जाने के बाद यदि कोई राशि शेष है तो उसमें से :

(रु) अंतरिती बैंक द्वारा निष्केप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत निगम से प्राप्त राशि तथा यदि निगम ने किसी राशि का प्रावधान किया हो तो वह राशि निगम को अदा करेगा और

(ख) जिन जमाकर्ताओं के संबंध में अंतरिती बैंक द्वारा निगम से राशियां प्राप्त की गयी हैं, उनके वसूली लेखों में देय राशियां और ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके संबंध में अंतरिती बैंक द्वारा निगम से राशियां प्राप्त की गयी हैं या निगम द्वारा जिनका प्रावधान किया गया है, निगम द्वारा दी गयी राशि या उसके लिए किये गये प्रावधान के संबंध में उक्त खातों से निगम को देय राशि के उपर्युक्त उप खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार

पहले अदा कर देने के बाद उनके वसूली खाते में उसे देय शेष राशि यदि कोई हो, अदा करेगा;

परंतु शर्त यह है कि निगम को देय राशि का, यदि ऐसा आवश्यक है तो, अंतरिती बैंक की बहियों में प्रावधान किया जायेगा और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य नियमावली, 1961 के विनियम 22 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से उसका निगम को भुगतान किया जायेगा।

आगे यह भी शर्त है कि अंतरिती बैंक ऊपर खंड (ख) में उल्लिखित राशियों का भुगतान करेगा।

- (1) यदि पैराग्राफ 6 के खंड (ख) में उल्लिखित तदनुरूपी या समान खाता बंद नहीं किया गया है या भुगतान हेतु अवधिपूर्ण नहीं हुआ है तो उस खाते में जमा प्रदान करके, और
- (2) यदि उक्त खाता बंद कर दिया गया है या भुगतान हेतु अवधिपूर्ण हो गया है तो नकद रूप में ।

(vi) ऊपर खंड (v) के उपखंड (क) के अनुसार निगम को देय राशियां और उक्त खंड के उपखंड (ख) के अनुसार जगाकर्ताओं के वसूली खातों में देय राशियां आपस में समान स्तर की होंगी, यदि उनका पूरा भुगतान नहीं हो सकता है तो उनमें समान अनुपात में कमी की जायेगी।

(vii) इस पैराग्राफ के खंड (v) में उल्लिखित राशियों का पूरा भुगतान हो जाने या उनका पूरा प्रावधान हो जाने के बाद अंतरिती बैंक उक्त खंड (v) में उल्लिखित शेष राशियों में से जो उसके पास उपलब्ध होंगी, नीचे विनिर्दिष्ट तरीके से और सीमा तक अंतरक बैंक के भूतपूर्व अंशधारकों के खातों में यदि कोई राशियां देय हों तो उनका समानुपातिक आधार पर भुगतान करेगा :

(क) पहले स्थान पर, अंतरक बैंक के पूर्व अधिमान अंशधारकों के खातों में देय राशि, यदि कोई हो, जब तक कि सभी खातों के प्रति पूरी अदायगी न कर दी गयी हो;

(ख) दूसरे स्थान पर, अंतरक बैंक के पूर्व साधारण अंशधारकों के खातों में देय राशि, यदि कोई हो, जब तक कि सभी खातों के प्रति पूरी अदायगी न कर दी गयी हो, और उसके बाद

(ग) तीसरे स्थान पर, अंतरक बैंक के पूर्व आस्थगित अंशधारकों के खातों में देय राशि, यदि कोई हो, जब तक कि सभी खातों के प्रति पूरी अदायगी न कर दी गयी हो;

(घ) उक्त खंड (क)(ख) और (ग) में उल्लिखित सभी राशियां पूरी तरह अदा कर दिये जाने के बाद अंतरिती बैंक के पास बचा अधिशेष, यदि कोई हो, अंतरक बैंक के पूर्व साधारण अंशधारकों के बीच समानुपातिक आधार पर वितरित किया जायेगा;

बशर्ते यदि ऐसा कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या उक्त किसी उप खंड में उल्लिखित खाते के प्रति कोई राशि देय है तो इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा जायेगा तथा उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

- (viii) इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट वसूली खातों में देय राशि इस योजना में उल्लिखित सीमा तक ही अंतरिती बैंक की देयता मानी जायेगी;
- (ix) निर्धारित तिथि से बारह साल की समाप्ति पर अथवा ऐसी पूर्व अवधि में जैसा केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करे, इस पैराग्राफ के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी ऐसी मद का, जिसकी वसूली उस तारीख तक न की गयी हो, मूल्यांकन अंतरिती बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा तथा अंतरिती बैंक उस मूल्यांकन में निर्धारित किसी राशि या राशियों का वितरण पहले इस पैराग्राफ के खंड (iv) में निर्दिष्ट देयताएं पूरी करने के लिए आवश्यक ऐसी किसी राशि की, जो उस तारीख को पूरी न की जा सकी हो, कटौती करने के बाद उक्त खंड (v), (vi) और (vii) में उल्लिखित क्रम और पद्धति से करेगा।
- (x) अंतरिती बैंक पिछले खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित मदों से वसूली गयी ऐसी राशियों का, जिनकी आवश्यकता तात्कालिक अदायगी के लिए नहीं पड़ेगी, अपने पास अथवा किसी अन्य बैंक या बैंकों के पास ऐसे रूप में और ऐसी अवधियों के लिए ब्याज वाहक जमाराशियों में निवेश करेगा, जैसा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त हो अथवा जैसा निदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाये। प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग खंड (iv), (v), (vi) और (vii) में निर्दिष्ट देयताएं, उनमें निर्दिष्ट तरीके से, पूरी करने के लिए किया जायेगा;
- (xi) किसी व्यक्त या अव्यक्त संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, पैराग्राफ 6 के अनुसार अंतरिती बैंक के पास खोले गये नये खातों के संबंध में ब्याज की अदायगी की जायेगी तथा उसे उसके या अगले पैराग्राफों के प्रावधानों के अनुसार तथा अंतरिती बैंक द्वारा अनुमत दरों पर जमा किया जायेगा;
- (xii) अंतरक बैंक का कोई भी जमाकर्ता अथवा अन्य लेनदार इस योजना द्वारा निर्धारित सीमा को छोड़कर उसके प्रति अंतरक बैंक की किसी भी देयता के संबंध में अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक से अन्य कोई भी मांग करने का हकदार नहीं होगा।

अध्याय V

अंतरक बैंक के कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व

8. कर्मचारियों की सेवा जारी रखना

(1) अंतरक बैंक के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे तथा यह माना जायेगा कि उन्हें अंतरिती बैंक में उन्हीं परिलिखियों तथा सेवा की उन्हीं शर्तों पर नियुक्त किया गया है जो कि 22 जनवरी 2002 को कारोबार की समाप्ति के ठीक पहले ऐसे कर्मचारियों पर लागू थीं।

बशर्ते अंतरक बैंक के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने निर्धारित तारीख, जब केंद्रीय सरकार द्वारा योजना मंजूर की गयी, के बाद एक माह की समाप्ति से पहले किसी भी समय अंतरक बैंक अथवा अंतरिती बैंक को दी गयी लिखित नोटिस द्वारा अंतरिती बैंक का कर्मचारी न बनने का अपना इरादा व्यक्त किया हो, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अंतर्गत किसी ऐसी क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, तथा ऐसी पेशन, उपदान, भविष्य निधि और सेवा निवृत्ति विषयक अन्य प्रकार के लाभों के हकदार होंगे जो 22 जनवरी 2002 को कारोबार की समाप्ति से तुरंत पहले लागू अंतरक बैंक के नियमों या प्राधिकारों के अंतर्गत सामान्यतः देय होते ।

(2) अंतरक बैंक के जिन कर्मचारियों को अंतरिती बैंक के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त माना गया हो, उनके संबंध में यह भी माना जायेगा कि अंतरिती बैंक ने उनकी छँटनी संबंधी क्षतिपूर्ति का वायित्व भी ले लिया है । ऐसा उस स्थिति में होगा जब अंतरिती बैंक की सेवा में रहते हुए उनकी छँटनी की गयी हो तथा इस आधार पर होगा कि उनकी सेवाएं निरंतर बनी रही हों और अंतरिती बैंक में उनके स्थानांतरण के कारण उनमें कोई व्यवधान न आया हो ।

(3) जिन कर्मचारियों की सेवाएं उप-पैराग्राफ (1) के अधीन अंतरिती बैंक में जारी रहेंगी उन्हें अंतरिती बैंक निर्धारित तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि बीतने पर वही परिलक्ष्यां अदा करेगा तथा वही सेवा शर्ते प्रदान करेगा जो अंतरिती बैंक के उसी श्रेणी या स्तर के तदनुरूपी कर्मचारियों पर लागू होंगी, परंतु शर्त यह होगी कि अंतरक बैंक के उक्त कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव अंतरिती बैंक के अन्य समकक्ष कर्मचारियों जैसा अथवा उनके समान हो ।

बशर्ते यदि इस संबंध में कोई संदेह अथवा मतभेद उत्पन्न हो कि क्या उपर्युक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी की योग्यता अथवा अनुभव अंतरिती बैंक के उसी श्रेणी या उसी स्तर के अन्य कर्मचारियों की योग्यता तथा अनुभव के जैसा अथवा समकक्ष ही है या नहीं अथवा यदि अंतरिती बैंक के वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के लिए अपनाये जाने वाले सिद्धांतों की प्रक्रिया के बारे में कोई संदेह अथवा मतभेद उत्पन्न हो तो ऐसे संदेह अथवा मतभेद को भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा जायेगा, जिसका निर्णय उस संबंध में अंतिम होगा ।

(4) अंतरक बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित किसी भविष्य निधि और / अथवा उपदान निधि के न्यासी अथवा प्रशासक अथवा, यथास्थिति, अंतरक बैंक, निर्धारित तारीख को अथवा निर्धारित तारीख के बाद यथाशीघ्र अंतरिती बैंक के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि और / अथवा उपदान निधि के न्यासियों को अथवा अन्य प्रकार से, जैसा भी अंतरिती बैंक निर्देश दे, अंतरक बैंक के कर्मचारियों के लाभार्थ न्यास में रखे हुए सारे धन एवं निवेशों को अंतरित कर देंगे / देगा ।

बशर्ते ऐसे परवर्ती न्यासी, योजना आरंभ होने के पूर्व निवेशों के मूल्य में हुई किसी कमी अथवा किये गये किसी कार्य, उपेक्षा अथवा चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे ।

अध्याय VI

विविध

9. ऋणदाताओं द्वारा मांग :

अंतरक बैंक का कोई भी ऋणदाता अंतरक बैंक अथवा अंतरिती बैंक के विरुद्ध उसके प्रति अंतरक बैंक की किसी जिम्मेदारी के संबंध में ऐसी कोई भी मांग करने का हकदार नहीं होगा जो इस योजना द्वारा निर्धारित न हो ।

10. केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, अंतरिती या अंतरक बैंक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही :

इस योजना के अनुसरण में सद्भाव से की गयी अथवा की जानेवाली किसी बात के लिए कोई भी वाद अथवा कानूनी कार्रवाई केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अंतरिती बैंक या अंतरक बैंक के विरुद्ध नहीं की जायेगी ।

11. अंतरक बैंक की शाखाओं का पुनर्गठन :

अंतरिती बैंक को यह विकल्प होगा कि वह अपनी सुविधा के अनुसार अंतरक बैंक की शाखाओं का समेकन करे और / अथवा अंतरक बैंक की घाटे में चलेनवाली वर्तमान शाखाओं को बंद कर दे अथवा स्थानांतरित कर दे । तथापि यह विकल्प अंतरिती बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से एक वर्ष में अपनाया जायेगा ।

12. विवरण तथा जानकारी देना :

अंतरिती बैंक इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले विवरण तथा जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा ।

13. उक्त योजना के कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे गये किसी प्रश्न / मुद्दे के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा ।

14. सूचना (नोटिस) देने का तरीका :

जब तक कि अंतरिती बैंक की बहियों में नया पता दर्ज न हो, तब तक अंतरिती बैंक द्वारा दिये जाने के लिए अपेक्षित कोई नोटिस अथवा अन्य सूचना यदि अंतरक बैंक की बहियों में दर्ज पते पर पूर्व अदायगी वाली सामान्य डाक से प्रेषिती को संबोधित हो एवं भेजी गयी हो तो वह विधिवत दी गयी सूचना मानी जायेगी तथा ऐसा नोटिस डाक द्वारा भेजे जाने के अड़तालीस घंटे के बाद मिला हुआ माना जायेगा। साथ ही, सामान्य हित का कोई नोटिस अथवा सूचना एक या अधिक ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा जो कि उन स्थानों पर परिचालन में होंगे जहां अंतरक बैंक अपना कारोबार कर रहा था।

[फा. सं. 15/2/2000-बोओए (i)]

शेखर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BANKING DIVISION)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2002

S.O. 648(E).—Whereas on an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government has made under sub-section (2) of that section, an order of moratorium in respect of the Benares State Bank Ltd., Varanasi;

And whereas during the period of moratorium, the Reserve Bank of India, being satisfied that in public interest and in the interest of the depositors it is necessary so to do, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 45 of the said Act had prepared a scheme for the amalgamation of the Benares State Bank Ltd., with the Bank of Baroda;

And whereas the Reserve Bank of India, after having sent the said scheme in draft to the banks concerned in accordance with the provisions of sub-section (6) of the said section and after having considered the suggestions and objections received in regard to the said scheme, had forwarded it to the Central Government for sanction;

And whereas the Central Government have considered the suggestions and objections in the light of the comments made by the Reserve Bank of India on the said suggestions and objections;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 45 of the said Act, the Central Government hereby sanctions following scheme on and subject to the terms and conditions hereafter mentioned.

Chapter – I

Preliminary

1. Short title and commencement:

- (1) This Scheme may be called Benares State Bank Ltd., (Amalgamation with Bank of Baroda) Scheme, 2002.
- (2) It shall come into force on such date (hereinafter referred to as the prescribed date) as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

2. Definitions:

In this Scheme, unless the context otherwise requires –

- (1) "Act" means the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
- (2) "Asset Account" means a notional account opened pursuant to sub-paragraph (2) of paragraph 5 of the Scheme for the purpose of ascertaining the surplus or shortfall after the adjustment from time to time of liabilities of the transferor bank as provided in the scheme;
- (3) "Collection Account" means a notional account opened in accordance with paragraph 7 of the Scheme, for the purpose of ascertaining the amount, if any, available for distribution to the members of the transferor bank after adjustment of assets and liabilities.
- (4) "Prescribed date" means the date which the Central Government may specify under sub-paragraph (2) of paragraph 1.

- (5) "Scheme" means the Benares State Bank Ltd. (Amalgamation with Bank of Baroda) Scheme, 2002;
- (6) "Transferor Bank" means the Benares State Bank Ltd., a banking company having its Registered Office at Varanasi;
- (7) "Transferee Bank" means the Bank of Baroda, a corresponding new bank constituted under Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;
- (8) Words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Chapter -II

Transfer of business, properties, assets and liabilities

3. Transfer of assets and liabilities and general effect thereof:

- (1) As on and from the prescribed date, all rights, powers, claims, demands, interests, authorities, privileges, benefits, assets and properties of the transferor bank, movable and immovable, including premises subject to all incidents of tenure and to the rents and other sums of money and covenants reserved or contained in the leases or agreements under which they are held, office furniture, loose equipment, plant apparatus and appliances, books papers, stocks of stationery, other stocks and stores, all investments in stocks shares and securities, all bills receivable in hand and in transit , all cash in hand and on current or deposit accounts (including money at call or short notice) with banks, bullion, all book debts, mortgage debts and other debts with the benefit of securities or any guarantee therefor, all other, if any, property rights and assets benefit of all guarantees in connection with the business of the transferor bank shall, subject to the other provisions of this scheme, stand transferred to, and become the properties and assets of the transferee bank; and

from the prescribed date, all the liabilities, duties and obligations of the transferor bank shall be and shall become the liabilities, duties and obligations of the transferee bank to the extent and in the matter provided hereinafter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, all contracts, deeds bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the prescribed date shall be effective to the extent and in the manner hereinafter provided against or in favour of the transferee bank and may be acted upon as if instead of the transferor bank, the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank.

(3) If on the prescribed date any suit, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the transferor bank is pending; the same shall not abate, or be discontinued or be in any way prejudicially affected, but shall, subject to the other provisions of this scheme, be prosecuted and enforced by or against the transferee bank.

(4) If according to the laws of any country outside India, the provisions of this scheme, by themselves, are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor bank to or in the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such assets or liability shall, on the prescribed date, stand entrusted to the Chief Executive Officer for the time being of the transferee bank and the Chief Executive Officer may exercise all powers and do all such acts and things as would have been exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively winding up its affairs. The Chief Executive Officer shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting and in connection therewith, the Chief Executive Officer may, either himself or through any person authorised by him in this behalf, realise any assets or discharge any liability of the transferor bank and transfer the net proceeds thereof to the transferee bank.

4. Closure of books of the transferor bank and preparation of balance sheet :

(1) The books of the transferor bank shall be closed and balanced and balance sheet prepared in the first instance as at the close of business on 22 January 2002 and thereafter as at the close of business on the date immediately preceding the prescribed date and the balance sheet shall be got audited and certified by a chartered accountant or a firm of chartered accountants approved or nominated by the Reserve Bank of India for the purpose.

(2) A copy of the balance sheet of the transferor bank prepared in accordance with the provisions of the foregoing paragraph, shall be filed by the transferor bank with the authority under the Companies Act, 1956 as soon as possible after it has been received and thereafter the transferor bank shall not be required to prepare balance sheet or profit and loss accounts, or to lay the same before its members or file copies thereof with the authority under the Companies Act, 1956 or to hold any board meeting or annual general meeting for the purpose of considering the balance sheet and accounts or for any other purpose.

5. Valuation of assets and determination of liabilities:

The transferee bank shall, in consultation with the transferor bank, value the assets and reckon the liabilities of the transferor bank in accordance with the following provisions, namely:

(1) (a) Investments other than Government Securities shall be valued at the market rates prevailing on the day immediately preceding the prescribed date.

(b) (i) Government Securities shall be valued as on the day immediately preceding the prescribed date in accordance with the principles laid down in the

notification issued by Reserve Bank of India for the purpose of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949.

(ii) The Securities of the Central Government such as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued under the small savings scheme of the Central Government shall be valued at their face value or the encashable value as on the said date, whichever is higher.

(iii) Where the market value of any Government Security such as the Zamindari Abolition Bonds or other similar security in respect of which the principal is payable in instalments is not ascertainable or is, for any reason, not considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such amount as is considered reasonable having regard to the instalments of principal and interest remaining to be paid, the period during which such instalments are payable, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity, and other relevant factors.

(c) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period.

(d) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investments is not ascertainable, only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of the issuing concern, the dividends paid by it during the preceding five years and other relevant factors.

(e) Premises and all other immovable properties and any assets acquired in satisfaction of claims shall be valued at their market value.

(f) Furniture and fixtures, stationery in stock and other assets, if any, shall be valued at the written down value as per books or the realisable value as may be considered reasonable.

(g) Advances, including bills purchased and discounted, book debts and sundry assets, will be scrutinised by the transferee bank and the securities, including guarantees, held as cover therefor examined and verified by the transferee bank. Thereafter the advances, including portions thereof, will be classified into two categories namely, "Advances considered good and readily realisable" and "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful of recovery".

(2) The transferee bank shall open on the prescribed date an account styled as 'Asset Account'. The aggregate amount representing the value of the assets determined as readily realisable assets in accordance with this clause shall be credited to the "Asset Account".

(3) (i) Where the valuation of any asset cannot be determined on the prescribed date, it may, with the approval of the Reserve Bank of India, be treated partly or wholly as an asset realisable at a later date.

(ii) In the event of any disagreement between the transferee bank and the transferor bank as regard the valuation of any asset and / or the classification of any advance and / or the determination of any liability, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India, whose opinion shall be final, provided that until such an opinion is received, the valuation of the item or portion thereof by the transferee bank shall provisionally be adopted for the purpose of this scheme.

(iii) It shall be competent for the Reserve Bank of India, in the event of its becoming necessary to do so, to obtain such technical advice as it may consider to be appropriate in connection with the valuation of any such item of asset or determination of any such item of liability, and the cost of obtaining such advice shall be payable in full out of the assets of the transferor bank.

(4) Liabilities for purposes of this scheme shall include all contingent liabilities which the transferee bank may reasonably be expected or required to meet out of its own resources on or after the prescribed date.

(5) The valuation of the assets and the determination of the liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be binding on both the banks and the members and creditors thereof.

Chapter III

Payment to creditors and depositors

6. Discharge of liability of the transferor bank :

In consideration of the transfer of the assets of the transferor bank to the transferee bank, the transferee bank shall discharge the liabilities of the transferor bank to the extent mentioned in this and the following clauses, namely:

(a) Any sums deposited by any employee of the transferor bank with that bank as staff security deposits, together with interest, if any, accrued thereon upto the prescribed date and all other outside liabilities as on the prescribed date, excluding deposits, shall be paid or provided for in full.

Explanation

For the purpose of this sub-paragraph, interest payable on a deposit upto the prescribed date shall be regarded as part of the concerned deposit.

(b) In respect of every savings bank account or current account or any other deposit account by whatever name called with the transferor bank and every other account not covered by Clause (a), including the interest to extent payable under this scheme, the transferee bank shall open with itself on the prescribed date a

corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto the pro rata share available in respect of each of the accounts out of the assets referred to in paragraph 5 as valued for the purposes of this scheme on the prescribed date, after excluding from the said assets as so valued the advances considered not readily realisable, or bad or doubtful or recovery, any asset or portion of an asset not valued on the prescribed date and any amount needed for the payments or provisions mentioned at Clause (a) above and after adding to the said assets so valued, the aggregate amount of the payments made in terms of clause (a) (i) of paragraph 2 of the order of moratorium order dated the 22 January 2002 issued to the transferor bank.

Provided that any payment made from a deposit account, on or after the close of business on 22 January 2002 and before the prescribed date, shall be reckoned towards the amount to be credited under this sub-paragraph and, accordingly the amount to be credited shall be the pro rata share less the amount of such payment.

Provided further that where the transferee bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account it may with the approval of the Reserve Bank withhold the credit to be made in that account in terms of clause (b) above till the transferee bank is able to ascertain the correct balance in such account.

Explanation

The term 'pro rata' shall, insofar as it occurs in this paragraph, means in proportion to the respective amounts remaining due as at the close of business on the 22 January 2002 together with the interest payable upto the date immediately preceding the prescribed date and shall, insofar as it occurs elsewhere in this scheme, means 'in proportion to the respective amounts remaining due at the time of the payment or distribution'.

(c) After the credits referred to in clause (b) above have been afforded, the transferee bank shall, with the least possible delay but in any case not later than

three months from the prescribed date, furnish to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (hereinafter referred to as the Corporation) a list complying in all respects with the requirements of sub-section (1) of Section 18 of that Act and thereafter when amounts referred to sub-section (2) of Section 18 of that Act, are received from the Corporation, the transferee bank shall credit each of the accounts referred to in clause (b) above, within seven days from the date or dates on which the amounts are received, to the extent of the sums due to that account in accordance with sub-section (2) of Section 18 of that Act :

Provided that –

(i) If any account referred to in clause (b) above has been closed or has matured for payment at the time when any amount for credit to that account is received from the Corporation, the payment to the person entitled to the said amount shall be made by the transferee bank in cash;

(ii) In case the person entitled to any amount referred to in clause (b) above cannot be found or is not readily traceable, provision for the amount due to such person shall be made and accounted for separately on the books of the Corporation itself and it shall not be necessary for the Corporation to pay the amounts to the transferee bank unless the person entitled to the amount is found or traced and the Corporation has decided to make the payment in respect of that person through the transferee bank.

Chapter IV

7. Rights and liabilities of the members of the transferor bank:

(1) On the prescribed date, the entire amount of the paid-up capital and reserves of the transferor bank shall be treated as provision for bad and doubtful

debts and depreciation in other assets of the transferor bank and the rights of the members of the transferor bank, in relation to the transferee bank, shall be as provided for below :

In respect of –

- (A) every account mentioned in clause (b) of the preceding paragraph, the balance in the account, if any, remaining uncredited in terms of that clause and clause (c); and
- (B) every share in the transferor bank, the amount of which was treated as paid-up towards share capital by or on behalf of each shareholder immediately before the prescribed date and / or the amount and on account of the calls made by the transferee bank in pursuance of clause (i) below, shall be treated as a collection account and shall be entered as such, in the books of the transferee bank and payments against the account shall be made in the following manner, namely :
 - (i) (a) the transferee bank shall, in the first instance, call upon every person who on the prescribed date was registered as the holder of a deferred share in the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares and the calls in arrears, if any, and thereafter, if it is found to be so necessary, every person who was, as on the prescribed date, registered as the holder of an ordinary share of the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares or the calls in arrears, if any;
 - (b) the transferee bank shall take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the

amounts due under clause (a) above together with interest at six per cent per annum for the period the default ;

(ii) the transferee bank shall, in respect of the advances, bills purchased and discounted, book debts and sundry debts and other assets, which are classified as "Advances considered not readily realisable and / or bad or doubtful of recovery' or which are or may be realisable wholly or partly after the prescribed date in terms of paragraph 5 above, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce payment, and may

(a) enter into a compromise or arrangement with the debtor or any other person or write off any such debt or asset;

(b) sell or otherwise dispose of any securities transferred to it or any asset taken over by it.

(iii) the transferee bank shall, in addition, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts, if any, awarded as damages by the High Court against any promoter, director, manager or other officer of the transferor bank under Section 45L of the Act , read with Section 45H thereof ;

(iv) the transferee bank may, out of the realisation effected by it on account of the items mentioned in clauses (i), (ii)and (iii) above, make payment or provision in respect of any contingent liability to the extent that the provision made thereof under paragraph 6(a) proves to be inadequate, as also with the prior approval of the Reserve Bank, in respect of any liability whether contingent or absolute which was not assessed in terms of paragraph 5 above and has arisen or been discovered on or after the prescribed date ;

(v) the transferee bank shall out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in clauses (i), (ii) and (iii) above, after deducting

1960 GL/102-4

therefrom the expenditure incurred for the purpose and, with the approval of the Reserve Bank fo India, such other expenses as may be considered reasonable and the amount appropriate therefrom in terms of clause (iv) above, or out of the balance, if any, which may be available from out of the provision in respect of contingent liabilities as reckoned for the purpose of this scheme after the extent of such liabilities has finally been ascertained,

- (a) pay to the Corporation, the amount received by the transferee bank from the Corporation under sub-section (2) of Section 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, and the amount ,if any, provided for by the Corporation, and
- (b) pay in the case of depositors in respect of whom the amounts have been received by the transferee bank from the Corporation, the amounts due in respect of the collection accounts, and in the case of depositors in respect of the whom any amounts have been received by the transferee bank from the Corporation or have been provided for by the Corporation, the balance if any, due to them in their collection accounts after the amounts due from the said accounts to the Corporation in respect of the payment made or provided for by the Corporation have first been paid in accordance with the provisions of sub-clause (a) above;

Provided that the amount due to the Corporation shall, if it becomes necessary so to do, be provided for in the books of the transferee bank and be paid to the Corporation in the manner specified in clause (b) of regulation 22 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961;

Provided further that the transferee bank shall make the payments referred to in clause (b) above,

The interest accrued shall be applied for meeting the liabilities referred to in clauses (iv), (v) (vi) and (vii) in the manner indicated therein;

- (xi) notwithstanding anything to the contrary contained in any contract, express or implied, interest shall be paid in respect of the new accounts opened with the transferee bank in terms of paragraph 6 and credited in accordance with the provisions of that or the next succeeding paragraphs and at such rates as the transferee bank may allow;
- (xii) no depositor or other creditors of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent prescribed by this scheme.

Chapter V

Rights and obligations of the Employees of Transferor Bank

8. Continuation of services of the employees:

(1) All the employees of transferor bank shall continue in service and be deemed to have been appointed in the transferee bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, as were applicable to such employees immediately before the close of business on the 22 January 2002.

Provided that the employees of the transferor bank, who have by notice in writing given to the transferor or the transferee bank at any time before the expiry of one month next following the date on which the scheme has been sanctioned by the Central Government, intimated their intention of not becoming employees of the transferee bank, shall be entitled to the payment of such compensation, if any, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible

- (d) after all the amounts mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c) above have been paid in full, the surplus, if any, remaining in the hands of the transferee bank shall be distributed pro rata among the former ordinary shareholders of the transferor bank;

Provided that if any question arises whether any amounts are due against an account mentioned in any of the above sub-clauses, it shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereof shall be final.

- (viii) The amounts due to the collection accounts referred to in this paragraph shall be deemed to be a liability of the transferee bank only to the extent provided for in this scheme;
- (ix) on the expiry of twelve years from the prescribed date or such earlier period as the Central Government after consulting the Reserve Bank of India may specify for this purpose, any item referred to in clause (ii) of this paragraph which may not have been realised by that date shall be valued by the transferee bank in consultation with the reserve Bank of India and the transferee bank shall distribute any amount or amounts determined in the light of the valuation after deducting therefrom first any sum necessary for meeting the liabilities referred to in clause (iv) of this paragraph which may remain unsatisfied as on that date in the order and the manner provided in clauses (v), (vi) and (vii) above.
- (x) the transferee bank shall invest such moneys realised on account of items mentioned in the preceding clauses (i), (ii) and (iii) as are not likely to be required by it for immediate payment, in interest bearing deposits with itself or with any other bank or banks, in such manner and for such periods as may be appropriate having regard to the facts and circumstances of the case or as the Reserve Bank of India may direct.

- (1) if the corresponding or similar account mentioned in clause (b) of paragraph 6 has not been closed or has not matured for payment, by credit to that account, and
- (2) if the said account has been closed or has matured for payment, in cash.
- (vi) The amounts due to the Corporation in terms of sub-clause (a) of clause (v) above and the amounts due to the collection accounts of the depositors in terms of sub-clause (b) of that clause shall rank equally among themselves, and if they cannot be paid in full shall abate in equal proportions;
- (vii) After the payments referred to in clause (v) of this paragraph have been made or provided for in full, the transferee bank shall, out of the balance of the amounts referred to in clause (v) which may be available to it, make payment pro rata towards the amounts, if any, due to the accounts of the former shareholders of the transferor bank in the manner and to the extent specified below:
- (a) in the first place, the amounts, if any, due to the accounts of the former preference shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made ;
 - (b) in the second place, the amount, if any, due to the accounts of the former ordinary shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made; and thereafter
 - (c) in the third place, the amounts, if any, due to the accounts of the former deferred shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made;

under the rules or authorisations of the transferor bank as in force immediately before the close of business on the 22 January 2002.

(2) The transferee bank shall, in respect of the employees of the transferor bank who are deemed to have been appointed as employees of the transferee bank, be deemed also to have taken over the liability for them of retrenchment compensation in the event of their being retrenched while in the service of the transferee bank on the basis that their service has been continuous and has not been interrupted by their transfer to the transferee bank.

(3) The transferee bank shall, on the expiry of a period not longer than three years from the date on which the scheme is sanctioned, pay or grant to the employees of the transferor bank whose services are continued in the transferee bank under subparagraph (1), the same remuneration and the same terms and conditions of service as are applicable to the employees of corresponding rank or status of the transferee bank subject to the qualifications and experience of the said employees of the transferor bank being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank :

Provided that if any doubt or difference arises as to whether the qualifications or experience of any of the said employees are the same as or equivalent to the qualifications and experience of the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank or as to the procedure or principles to be adopted for the fixation of the pay of the employees in the scales of pay of the transferee bank, the doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(4) The trustees or administrators of any provident fund and/or gratuity fund constituted for the employees of the transferor bank, or as the case may be, the transferor bank, shall on or as soon as possible after the prescribed date transfer to the trustee of the employees' provident fund and/or gratuity fund constituted for the

transferee bank or otherwise as the transferee bank may direct, all the moneys and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank.

Provided that such latter trustees shall not be liable for any deficiency in the value of investments, or in respect of any act, neglect or default done before the date of commencement of the scheme.

Chapter VI
Miscellaneous

9. Demand by Creditors :

No creditor of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent prescribed by this scheme.

10. Legal proceedings against Central Government,

Reserve Bank of India, Transferee or Transferor bank :

No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government, the Reserve Bank of India or the transferee bank or the transferor bank for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this scheme.

11. Reorganisation of branches of transferor bank :

The transferee bank shall have the option of integrating branches of transferor bank according to its convenience and / or close down or shift the existing branches of the transferor bank. The aforesaid option will, however, be exercised by the transferee bank with the prior approval of Reserve Bank of India.

12. Furnishing statements and Information :

The transferee bank shall submit to the Reserve Bank of India such statements and information as may be required by the Reserve Bank of India from time to time regarding the implementation of this scheme.

13. Any question or issue on the implementation of the Scheme, if referred to the Reserve Bank of India, the decision of the Reserve Bank of India thereon shall be final.

14. Manner of service of notice:

Any notice or other communication required to be given by the transferee bank shall be considered to be duly given if addressed and sent by pre-paid ordinary post to the addressee at the address registered in the books of the transferor bank, until a new address is registered in the books of the transferee bank, and such notice shall be deemed to be served on the expiry of forty eight hours after it has been posted. Any notice or communication which is of general interest shall be advertised, in addition, in one or more daily newspapers which may be in circulation at the places where the transferor bank was transacting its business.

[F. No. 15/2/2000-BOA (i)]

SHEKHAR AGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2002

[F.No. 15/2/2000-BOA(i)]

का.आ. 649(अ).—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, बनारस स्टेट बैंक लिO (बैंक आफ बड़ौदा में समामेलन) स्कीम, 2000 जिसे उपर्युक्त उपधारा के प्राक्षानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है :-

(क) 20 जून, 2002 को उस तारीख के रूप में जिस तारीख को पैराग्राफ 6 को छोड़कर सभी पैराग्राफ प्रभावी होंगे, और

(ख) 19 जुलाई, 2002 को उस तारीख के रूप में जिस तारीख को पैराग्राफ 6 लागू होगा, विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 15/2/2000-बोओए (ii)]

शेखर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2002

S.O. 649(E).—In pursuance of sub-section (7) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby specifies –

- (a) the 20th June, 2002 as the date on which all paragraphs, except paragraph 6, and
- (b) the 19th July, 2002 as the date on which paragraph 6,

of the Benares State Bank Ltd. (Amalgamation with Bank of Baroda) Scheme, 2002, which has been sanctioned by the Central Government under the provisions of the said sub-section, shall come into force.

[F No. 15/2/2000-BOA (ii)]
SHEKHAR AGARWAL, Jr. Secy.

